

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

राजस्व अपील संख्या: 06/2019

दायर दिनांक: 19.09.2019

निर्णय दिनांक 01.03.2021

—:अनवान:—

श्री लक्ष्मणसिंह पिता स्व. पृथ्वीसिंह चदाणा निवासी सिरोही की भागल, गावगुडा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द

—:अपीलांट

—:बनाम:—

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील खमनोर जिला राजसमंद

—:रेस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 05.09.2019, न्यायालय तहसीलदार खमनोर प्रकरण संख्या 29/19 में पारित आदेश के विरुद्ध

उपस्थित:—

- 1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलांट
- 2— श्री कैलाश चन्द्र बौल्या, राजकीय अधिवक्ता

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट्स द्वारा ग्राम सिरोही की भागल तहसील खमनोर के आ०न० 1974 रकबा 18-10 बीघा व आ०न० 3386 रकबा 16-03 बीघा में से 10-00 बीघा भूमि पर अतिक्रमण करने संबंधी रिपोर्ट तहसीलदार, खमनोर को प्रस्तुत की गयी जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक: 05.09.2019 को अपीलांट की बैदखली व शास्ति 450/- आरोपित करने का आदेश पारित किया गया। इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय दिनांक: 16.09.2019 को पेश की गयी।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा बहस में यह बताया गया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय, प्रकरण में अपीलांट कि ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के विपरित जाकर आदेश पारित किया तथा अपीलांट को प्रकरण में न तो साक्ष्य पेश करने हेतु अवसर दिया गया तथा न ही बहस करने हेतु अवसर दिया गया, इसलिए आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त योग्य हैं। अपीलांट को जो सूचना पत्र नाजायज कब्जे के सम्बन्ध में दिया गया, उस सूचना पत्र में सन 1976 से अतिचार करना बताया जबकि प्रार्थी ने जो जवाब प्रस्तुत किया उसमें स्पष्ट बताया कि पेमाईशी से पूर्व मूल आराजी नं० 2529, जो कूल रकबा ईकरासी बिघा पन्द्रह बिस्वा किस्म बिलानाम




भूमि स्थित थी, उस आराजी नम्बर 2529 में से अपीलान्ट को 6 बीघा 14 बिस्वा भूमि कार्यालय उप जिलाधीश उदयपुर से आवंटन दिनांक 14.04.1975 को आवंटन कर, अपीलान्ट को मौके पर आधिपत्य सुपुर्द किया तथा अपीलान्ट को गैर खातेदार घोषित किया तब से अपीलान्ट का उक्त भूमि पर आधिपत्य चला आ रहा है, जिसे करीब 40 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, तथा अपीलान्ट की ओर से जवाब दस्तावेज अपीलान्ट को जो पट्टा मिला उसकी छायाप्रति तथा गत पेमाईशी नम्बर 2529 कि जमाबन्दी की नकल तथा उसका खसरा मिलान सभी दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन दस्तावेजों का बिना अवलोकन किये उक्त आदेश पारित कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाना फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खमनोर द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में अपीलान्ट को प्रकरण में न तो साक्ष्य पेश करने तथा न ही बहस करने तथा दस्तावेजों का बिना अवलोकन किये आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई का समुचित अवसर पक्षकारान को प्रदान नहीं किया है। अतः उक्त परिस्थिति में अपीलार्थी की उक्त अपील को स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करवाया जाना उचित समझता हूँ।


::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर तहसीलदार खमनोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2019 को खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार खमनोर को प्रतिप्रेषित (REMAND) कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को शहादत, सबूत एवं सुनवायी का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का पुनः नियमानुसार निस्तारण किया जावे।


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 01.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद